विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षक कर पाएगा गैर शैक्षणिक कार्य

नई शिक्षा नीति और नवीन शिक्षण सत्र को लेकर विभाग की चिंताएं

मंत्रालय में बैठक के दौरान अधिकारी भी मंत्री को दे चुके हैं सुझाव

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद दहलीज पर खड़े नवीन शिक्षण सत्र को लेकर राज्य सरकार चिंतित हुई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि विशेष परिस्थितियों में ही अब शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य कर पाएगा।

नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। विभाग इस बात को मान रहा है कि अगर नई नीति के तहत काम करना है तो कक्षा में विषय वार शिक्षकों की बेहद आवश्यकता है। यही कारण है कि आधा सप्ताह पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विधानसभा परिसर में मीडिया के समक्ष बोल चुके हैं कि नवीन शिक्षण सत्र से हम विद्यालयों में बड़ा बदलाव करेंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि प्रदेश भर में डीपीसी और बीआरसीसी की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही है। इसके साथ ही अब विभाग के अधिकारियों ने मंत्री का शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्य की ओर भी ध्यान दिलाया है। विधानसभा सत्र के पूर्व शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जब मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ले रहे थे, तब सबसे पहला मुद्दा नवीन शिक्षण सत्र के साथ शिक्षकों की कमी का आया था। तब आला अधिकारी यह सुझाव दे चुके हैं कि प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का अटैचमेंट है। डीपीसी और बीआरसीसी कार्यालयों में जहां शिक्षक प्रतिनियुक्ति के साथ-साथ अटैच हैं वही मंत्री और विधायकों के यहां भी शिक्षकों का ताबड़तोड़ आसंजन जारी है। अधिकारियों ने इस सुझाव को भी रखा की अगर अटैचमेंट समाप्त करने के बाद यह शिक्षक विद्यालयों में पहुंचते हैं तो बड़ी संख्या में बच्चों को कक्षाओं में पढ़ाई का सशक्त माध्यम जुट जाएगा।

विभाग प्रमुख सचिव भी लिख चुकी हैं पत्र

इधर बताना होगा कि पिछले वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी भी कलेक्टरों को पत्र लिख चुकी हैं। इस पत्र में साफ कहा गया था कि जो भी शिक्षक मुख्य संस्था छोड़कर दूसरी जगह अटैच हैं तो तत्काल स्कूलों में भेजा जाए। अगर शिक्षक स्कूल में नहीं पहुंचता है तब उसके खातों में वेतन राशि का भुगतान न किया जाए। पत्र की बाकायदा एक प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जय श्री कियावत भी पत्र के माध्यम से कलेक्टर को कह चुकी है कि विधायकों और मंत्रियों के यहां जो भी शिक्षक अटैच है। उन्हें तुरंत इस कार्य से मुक्त कर स्कूलों में भेजा जाए। अधिकारी मंत्री को यह भी बता चुके हैं कि बार-बार पत्र लिखने के बावजूद कलेक्टर शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त नहीं कर रहे हैं।

इनका कहना है...

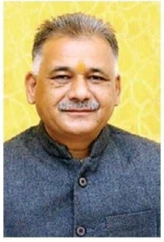

हमने तय किया है कि अब शिक्षक विशेष परिस्थितियों में ही गैर शैक्षणिक कार्य करेंगे। क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों का शैक्षणिक गुणात्मक विकास करने के लिए शिक्षकों के सहयोग की जरूरत है। जनगणना और मतदाता जैसे राष्ट्रीय कार्यों में ही शिक्षक को लगाया जाएगा।

-इंदर सिंह परमार, मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मप्र शासन

शिक्षकों ने कहा जब बच्चे नहीं आ रहे तो कैसे दिया जाएगा लक्ष्य के अनुसार रिजल्ट

रिजल्ट के लक्ष्य निर्धारण से दहशत में गुरु, विभाग से चर्चा की कवायद शुरू

आरोप लगाया है कि विभाग के अधिकारी हौसला तोड़ने वाले आदेश कर रहे जारी

भोपाल (आरएनएन)। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं बच्चों की परीक्षा परिणाम का लक्ष्य निर्धारण क्या किया शिक्षकों में चिंताएं देखी जा रही हैं। इसकी जमीनी वजह भी शिक्षक बता रहे हैं कि कोरोना के संकटकाल में जब बच्चे ही स्कूलों में नहीं आ रहे तो कैसे विभाग की मंशा को पूरा किया जाए। आरोप है कि इस प्रकार के आदेश शिक्षकों का साहस तोड़ रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार इस वर्ष कोविड-19 के संकट के चलते शैक्षणिक कार्य काफी प्रभावित हुआ है। मध्यप्रदेश में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों को खुले हुए मात्र दो माह ही हुए हैं। विद्यालयों में छात्र उपस्थिति की कोई अनिवार्यता ना होने के कारण अधिकांश विद्यालयों में छात्र उपस्थिति 10 से लेकर 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है। विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं प्राचार्य द्वारा लगातार प्रयास करने के बावजूद छात्र विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। बार-बार शिक्षक पालक संघ की बैठक में अभिभावकों से चर्चा करने के बावजूद अभिभावक छात्रों को विद्यालय भेजने के प्रति गंभीर नहीं है। इस स्थिति में विद्यालय खुले जरूर हैं, लेकिन अधिकतम 30 प्रतिशत छात्र ही लाभांवित हो पा रहे हैं। शेष 70 प्रतिशत छात्र विद्यालयों से लगातार अनुपस्थित है।

छात्र अनुपस्थिति के कारण शिक्षकों के समस्त शैक्षणिक एवं अकादमिक प्रयास निरर्थक हो रहे हैं। मेहनत करने के बाद भी शिक्षक अपने आप को बेहतर परीक्षा परिणाम देने में असहाय महसूस कर रहा है। इन कठिन परिस्थितियों में शिक्षक का आत्मबल एवं आत्मविश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षक के प्रति उदार एवं संवेदनशील रवैया अपनाने की आवश्यकता है, परन्तु आरोप है कि लोक शिक्षण संचालनालय मप्र भोपाल द्वारा अव्यावहारिक एवं अतार्किक आदेश प्रसारित कर शिक्षकों पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

ये दिया लक्ष्य

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशों में शिक्षकों को कक्षा 9वी में 59 प्रतिशत कक्षा दसवी में 64 प्रतिशत कक्षा ग्यारहवी में 81 और कक्षा 12वीं में 73 प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य से कम परीक्षा परिणाम आने पर शिक्षकों को दंडित करने का भी प्रावधान किया गया है। विभाग इस बात से भलीभांति परिचित हैं कि लक्ष्य शत-प्रतिशत छात्र उपस्थिति के आधार पर तय होता है ना कि छात्रों की मात्र 30 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जब विद्यालय में 70 प्रतिशत छात्र उपस्थित ही नहीं है तो फिर यह लक्ष्य किस आधार पर तय किया जा रहा है। इसी प्रकार विद्यालय में आयोजित हुई अर्द्धवार्षिक परीक्षा की समीक्षा कर विद्यालयों में डी और ई ग्रेड के छात्रों की निदानात्मक कक्षाएं लगाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री पिछले दिनों भोपाल में अध्यापकों के ही कार्यक्रम में बोल चुके हैं कि शिक्षकों की दक्षता परीक्षा को सकारात्मक भाव में लेना चाहिए। क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत हम भी चाहते हैं कि शिक्षक दक्ष हो, ताकि इसका लाभ बच्चों को मिल सके।

छात्रों की उपस्थिति कम तो कैसे शत-प्रतिशत परिणाम संभव: कौशल

शासकीय अध्यापक संघ के संयोजक उपेन्द्र कौशल का कहना है कि जब विद्यालयों में छात्र उपस्थित ही नहीं है तो किस परीक्षा परिणाम की समीक्षा की जाए और किस आधार पर निदानात्मक कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। यह एक गंभीर प्रश्न है। लोक शिक्षण संचनालय के निर्देश पर ही जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभाग प्रमुखों को विद्यालयों के शैक्षणिक एवं अकादमिक निरीक्षण करने हेतु आदेशित किया है। विगत डेढ़ माह से समस्त विभाग प्रमुख विद्यालयों में लगातार उपस्थित हो रहे हैं। इसके बावजूद किसी प्रकार का कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया है क्योंकि छात्र अनुपस्थिति के चलते समस्त प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं। कौशल का कहना है कि विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर पूरी जमीनी हकीकत से अवगत कराया जाएगा।

जमीनी हकीकत से दूर अफसरों के हाथों में कमान: दुबे

मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे का कहना है कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर अधिकारियों के हाथ मे शिक्षा विभाग की सम्पूर्ण कमान होने के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। इस करोना संकट काल में संपूर्ण देश में मध्य प्रदेश ही एक मात्र ऐसा प्रदेश है, जहां लगातार ऐसे अव्यावहारिक निर्णय लिए जा रहे हैं, जिनसे कोई सकारात्मक परिणाम या सुधार तो नहीं हो रहा है। बल्कि इन अतार्किक अव्यावहारिक निर्णय के चलते शिक्षकों पर मानसिक दबाव बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है जिससे वह पूर्ण मनोयोग से स्वतंत्र मानसिकता से अध्यापन कार्य भी नहीं करा पा रहा है।

विभाग की नीतियां पूरी तरह हो रहीं विफल: शर्मा

संगठन के प्रांतीय महामंत्री राजकुमार शर्मा ने कहा कि विद्यालयों में छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के बिना किए जा रहे समस्त प्रयास नीतियां एवं कार्य योजनाएं पूरी तरह विफल है। शर्मा के अनुसार शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन से कि शासन स्तर से कुछ ऐसी नीतियों का निर्धारण किया जाए जिसमें अभिभावकों को भी छात्र उपस्थिति के लिए पाबंद किया जाए एवं जिन छात्रों की उपस्थिति विद्यालय में 60 प्रतिशत से कम है। उनकी संख्या परीक्षा परिणाम के आंकलन में न जोड़ा जाये। विद्यालय के परीक्षा परिणाम का आंकलन विद्यालय में उपस्थित छात्र संख्या के आधार पर हो। व्यवहारिक स्थितियों का आंकलन किए बिना लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए जा रहे इन अतार्किक एवं व्यवहारिक आदेशों पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं शिक्षकों को बिना किसी दबाव के शैक्षिक कार्य किए जाने हेतु स्वतंत्र रखा जाए। इस सबंध में बार बार ज्ञापन देने के बावजूद आज तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। शिक्षकों का हौसला तोड़ने वाले एवं उन्हें प्रताड़ित करने वाले लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किए गए इन समस्त आदेशों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

Badri Gautam

बजट ब्रेकिंग... 2 मार्च को आएगा प्रदेश का बजट, दो दिन पहले जानिए क्या होगा इस बजट में, **सबसे पहले भास्कर में...**

पेट्रोल-डीजल व शराब पर न वैट घटेगा, न नया टैक्स लगेगा; 7.50 लाख कर्मचारियों को दो वेतनवृद्धि एक साथ मिलेंगी

- **2020 और 2021 की वेतनवृद्धि देने की घोषणा करेगी सरकार**
- **25% तक डीए की भी व्यवस्था करेगी, 4 से 5 हजार करोड़ का खर्च**
- **मंडला, छतरपुर, नीमच, शिवपुरी, राजगढ़ व मंदसौर में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज**
- **किसानों को राज्य की ओर से 4 हजार रु. सम्मान निधि अब बराबर मिलेगी**

अनिल गुप्ता | भोपाल

सस्ते पेट्रोल-डीजल के लिए प्रदेश बजट से आस लगाए बैठी जनता को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सरकार 2 मार्च को विधानसभा में जो बजट पेश करने जा रही है, उसमें पेट्रोलियम पदार्थों से वैट घटाने की घोषणा शामिल नहीं है। यानी पेट्रोल-डीजल पर सरकार अभी टैक्स नहीं घटा रही। न ही कोई नया टैक्स लगाएगी। शराब पर भी यही स्थिति रहेगी। बताया जा रहा है कि मई में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर सरकार ऐसा कर रही है। इस बजट में सरकार का पूरा फोकस प्रदेश के साढ़े सात लाख कर्मचारियों, चार लाख पेंशनर्स पर रहेगा। साथ ही आत्मनिर्भर मप्र के सभी चार सेक्टरों को मजबूत करने के प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट जुलाई 2021 के साथ देने की घोषणा बजट में होगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिकतम 25% डीए (महंगाई भत्ता) की व्यवस्था कर दी गई है यानी नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार यदि डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ा सकती है। यह राशि करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के बीच होगी। अभी केंद्र के 17% डीए के मुकाबले मप्र में 12% ही डीए है। राज्य सरकार बकाया 5% के साथ ही बढ़ा हुआ डीए भी दे सकती है। यह जरूर है कि जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) मिलने के बाद आगे तो वेतन बढ़ेगा, लेकिन पिछला एरियर न डीए का मिलेगा और न ही वेतनवृद्धि का। बजट की लगभग तैयारी हो गई है।

2 लाख 40 हजार करोड़ रु. तक का होगा बजट

इस बार बजट दो लाख 35 हजार करोड़ से दो लाख 40 हजार करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। यह पिछले साल के साइज की तुलना में सात से दस फीसदी तक बढ़ने वाला है। बजट में मप्र में नौ नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा होगी। इसमें से छह केंद्र सरकार की मदद से और तीन मप्र खोलेगा। ये शिवपुरी, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, दमोह और सिवनी में होंगे। वर्ष 2003 से पहले 5 थे। इसके बाद आठ नए चालू हुए। अब नौ नए खुलेंगे।

घोषणा... गैस पीड़ित विधवा महिला की पेंशन फिर शुरू होगी

गैस पीड़ित विधवा महिला को एक हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा बजट में हो सकती है। 2012-13 में 8 साल के लिए इसे केंद्र ने प्रारंभ किया था। फिर यह बंद हो गई। अब राज्य सरकार इसे शुरू करेगी।

एक्सप्रेस-वे... आसपास विकास के लिए प्रोत्साहन पैकेज लाएंगे

बजट में नर्मदा एक्सप्रेस-वे और अटल प्रोग्रेस वे के रास्ते में इकोनॉमिक कॉरिडोर व इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने के लिए नए प्रावधानों का उल्लेख होगा। राज्य सरकार इसके लिए प्रोत्साहन पैकेज की बात कर सकती है।

Badri Gautam

तीन मूल्यांकनकर्ता तीन साल के लिए परीक्षा कार्य से प्रतिबंधित

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की वर्ष 2020 बोर्ड परीक्षा में 12वीं की एक छात्रा की कॉपी बदलने के मामले में तीन मूल्यांकनकर्ताओं को तीन साल के लिए परीक्षा कार्य से प्रतिबंधित कर दिया गया है। छात्रा को एक विषय में पहले 20 अंक मिले थे, लेकिन पुनर्गणना के बाद 64 अंक मिले।

इस मामले में परीक्षक, उपमुख्य परीक्षक और मुख्य परीक्षक को परीक्षा वर्ष 2021, 2022 व 2023 के लिए मंडल द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी पारिश्रमिक संबंधी कार्यों से प्रतिबंधित किया है। तीनों उज्जैन जिले के शिक्षक हैं। अशासकीय संतमीर कान्वेंट स्कूल नयापुरा की शिक्षक शोभा सक्सेना, शासकीय उमावि महाराजवाड़ा के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक डीएस कनेल, शासकीय हाईस्कूल बघेरा के प्राचार्य राज कुमार पोरवाल को प्रतिबंधित किया गया है।

मामला 2020 की 12वीं बोर्ड परीक्षा का है। कॉमर्स की छात्रा यामिनी शर्मा को एक विषय में 20 अंक मिले थे, उन्हें सप्लीमेंट्री आ गई। छात्रा ने बोर्ड से पुनर्गणना और उत्तरपुस्तिका देखने के लिए आवेदन किया तो पता चला कि कॉपी बदली हुई थी। रोल नंबर में भी कांट छांट की गई थी। कॉपी में हस्तलिपि, परीक्षा कक्ष क्रमांक से लेकर परीक्षा की तारीख तक गलत थी। फिर से कॉपी जांच के बाद छात्रा को उस विषय में 64 अंक मिले और छात्रा द्वितीय श्रेणी से पास हुई।

मामले में जांच के बाद कार्रवाई की गई है। अब छात्रा को हर्जाना देने और शिक्षकों को जुर्माना देना होगा, ऐसा प्राविधान है कि नहीं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। **– उमेश कुमार सिंह**, सचिव, माशिमं

Badri Gautam

आंसरशीट बदलने से फेल हुई थी छात्रा, जांच के बाद मिले 64 नंबर

12वीं बोर्ड का मामला, 3 शिक्षकों पर कार्रवाई

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

वर्ष 2019-20 की परीक्षा में 12वीं कॉमर्स की छात्रा की आंसरशीट बदलने के मामले में एमपी बोर्ड ने 3 शिक्षकों को 3 साल के लिए डिबार (प्रतिबंधित) कर दिया है। तीनों शिक्षक इस दौरान किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं बन सकेंगे।

12वीं बोर्ड परीक्षा में कॉमर्स की छात्रा यामिनी शर्मा को एक विषय में सिर्फ 20 नंबर मिले थे, जिससे एक विषय में पूरक आ गई थी। छात्रा ने पुनर्गणना और आंसरशीट देखने के लिए आवेदन किया तो वह हैरान रह गई। उसकी कॉपी बदली हुई थी और रोल नंबर में छेड़छाड़ की गई थी। कॉपी में लिखावट, परीक्षा कक्ष क्रमांक से लेकर परीक्षा की तारीख तक गलत थी। जांच के बाद छात्रा को उस विषय में 64 नंबर मिले हैं। इस मामले में मंडल ने निर्देश जारी किए हैं कि मूल्यांकन संबंधी कार्य अत्यंत संवेदीनशील प्रकृति का है। इससे सीधे तौर पर विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा रहता है। इस मामले में उज्जैन जिले के शिक्षकों शोभा सक्सेना, डीएस कनेल, और राज कुमार पोरवाल को प्रतिबंधित किया गया है।

Badri Gautam

प्राइवेट स्कूलों में इस बार नहीं बनेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर

निजी स्कूल संचालकों ने बताया परेशानी वाला निर्णय

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

मो.नं. 9893231237

एमपी बोर्ड कोरोनाकाल में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के साथ एक और प्रयोग करने जा रहा है। अब प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स को अन्य स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। अभी तक स्टूडेंट्स को उनके स्कूलों में ही प्रैक्टिकल एग्जाम की सुविधा थी। मंडल नए सेंटर तय करेगा।

ज्ञात हो कि कोरोना व लॉकडाउन के कारण स्कूलों में साल भी नियमित कक्षाएं नहीं लगी हैं। अभी, स्कूल खुलने के बाद भी अधिकांश स्टूडेंट घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। यह स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार कर पाए हैं। अभी भी परिस्थितियां सुधरी नहीं

हैं। ऐसे में मंडल स्कूलों की प्रयोगशालाओं के निरीक्षण और वहां के बच्चों को अन्य स्कूलों में भेजकर प्रैक्टिल एग्जाम कराने की तैयारी कर रहा है। मंडल के सचिव ने कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित आदेश जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि कई विद्यार्थी कोरोना संक्रमण के कारण आज भी स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रायोगिक परीक्षा को इतना कठिन कर देना गलत है।

Badri Gautam

हाई एवं हायर सेकंड्री की प्रायोगिक परीक्षा 15 अप्रैल से

भास्कर न्यूज. **सतना**

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होंगी। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा मूल्यांकनकर्ताओं की ड्यूटी 5 मार्च से लगाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए टाइम टेबिल के अनुसार 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से आयोजित की जाएंगी। इस बार बोर्ड की परीक्षा पिछले वर्ष की अपेक्षा सुबह 1 घंटे पहले शुरू होगी यानि कि 9 बजे की बजाय 8 बजे से परीक्षा आयोजित की जाएंगी। वहीं इस बार यदि शासन द्वारा कोई सार्वजनिक या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत कार्यक्रमानुसार संपन्न होंगी।

लैब में नहीं हुए प्रैक्टिकल

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल तो जरूर खोल दिए गए थे, मगर उसके साथ एक शर्त भी जोड़ी गई थी कि जो छात्र अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर आएंगे, वही स्कूल में प्रवेश कर सकेंगे। इस वजह से स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति भी प्रभावित हुई। परीक्षा को लेकर शिक्षकों द्वारा तैयारियां तो कराई गईं, मगर छात्रों के पै्रक्टिकल लैब में नहीं हो सके। शिक्षकों ने बताया कि छात्रों को सैद्धांतिक तौर पर पै्रक्टिकल की जानकारी दी गई है।

Badri Gautam

कृषि मंत्री कमल पटेल ने चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख को दी श्रद्धांजलि

ग्रामोदय किसान स्कूल का किया शिलान्यास

भोपाल, (प्रसं)। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने शनिवार को चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री पटेल दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामोदय किसान स्कूल भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरिश गौतम भी उपस्थित थे। मंत्री श्री पटेल ने विद्यार्थियों से भी भेंट की। उन्होंने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

कृषि मंत्री श्री पटेल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश के 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ की राशि वितरण के लिए दमोह में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में चित्रकूट से शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस समारोह में किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। चित्रकूट में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल से सतना के युवा कृषक लवकुश यादव ने भेंट की।

श्री यादव से मंत्री श्री पटेल ने सीढ़ीदारनुमा खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस खेती से श्री यादव चुरिया नामक गेहूं की फसल लेते है, जो बारिश के पानी पर निर्भर करती है। किसान ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि से एक पोषण वाटिका भी बनाई जिससे परिवार को वर्ष भर सब्जी की उपलब्धता बनी रहती है। मंत्री श्री पटेल ने युवा कृषक को हरसंभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया।

Badri Gautam

इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक टीचर के 600 पद खाली, कैसे बढ़ेगी गुणवत्ता

ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

तकनीकी शिक्षा विभाग के आधा दर्जन इंजीनियरिंग व 69 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में भर्तियों में करीब एक साल से रोक लगी है। इसके चलते लेक्चरर के करीब 600 रिक्त पद खाली हैं। इसके पीछे ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण का नोटिफिकेशन न जारी होना बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारी इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक में फैकल्टी के अभाव में शैक्षणिक गतिविधियां चौपट हैं। भर्ती में डीटीई को दो प्रमुख नियमों से परेशानी हो रही है। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया अटकी है। जीएडी और शासन से स्पष्ट आदेश नहीं होने से अधिकारी पशोपेश में हैं। डीटीई को इन कॉलेजों में करीब 600 लेक्चरर की भर्ती करना है। इसमें 500 पॉलीटेक्निक और करीब 100 पद इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त हैं। वित्त विभाग ने तीन साल में 180-180 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ये कालेज सोसायटी के रूप चल रहे हैं। इसमें प्राचार्य, एचओडी और लेक्चरार के एक-एक पद हैं। इसमें इन कॉलजों को एक-एक यूनिट बनाकर भर्ती करने से रोस्टर का पालन नहीं होगा।

Badri Gautam

पीएससी मामले में अर्जेंट सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार

जबलपुर। पीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षाओं के संबंध में दायर मामलों की त्वरित सुनवाई किए जाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पीएससी को लेकर दायर मामलों में हाईकोर्ट ने आगामी 15 मार्च को मामलों की संयुक्त सुनवाई निर्धारित की थी। जिस पर आवेदक के अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह ने गत दिवस हाईकोर्ट को आवेदन देकर कहा था कि पीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन 22 मार्च को होना है, इसलिए उक्त मामलों में त्वरित सुनवाई किए जाने की प्रार्थना की गई थी। जिस पर न्यायालय ने त्वरित सुनवाई से इंकार करते हुए 15 मार्च को निर्धारित तिथि पर सुनवाई किए जाने की व्यवस्था दी है।

Badri Gautam

बजट पर टिकी कर्मचारियों की निगाहें, बोले महंगाई तोड़ रही कमर

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

मौजूदा सप्ताह के दौरान विधानसभा में पेश होने जा रहे बजट पर कर्मचारियों की निगाहें टिक गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है। उसने शासकीय सेवकों से लेकर आमजनों की कमर तोड़कर रख दी है।

कर्मचारियों का कहना है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए हो गए हैं। घरेलू गैस साढ़े आठ सौ रुपए पार कर रहा है। प्रदेश में अधिकारी-कर्मचारियों का कहना है कि मध्यम वर्ग व नौकरीपेशा को महंगाई चिंता में डाल रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, मालभाड़ा, परिवहन सहित चौतरफा महंगाई ने तांडव मचा रखा है। कर्मचारी जगत को महंगाई से सामना करने व वेतन स्तर व क्रय शक्ति बनाये रखने के लिए डीए-डीआर की मूल्य सूचकांक आधारित प्रति छः माही गणना पद्धति विद्यमान है। कोरोना के चलते इसे स्थगित करने से केंद्र में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 17 व राज्य में 12 प्रतिशत डीए डीआर पर रोक रखा है। वर्तमान में यह नियमित भुगतान की स्थिति में 28 फीसदी होना चाहिए था। इसी प्रकार 3 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि भी स्थगित है। कुल मिलाकर कम वेतन व बेशुमार महंगाई से क्रय शक्ति का प्रभावित होने से जीवन दूभर हो रहा है।

गृहभाड़ा, लंबित डीए, वेतनवृद्धि सहित अन्य मांगों के पूरा होने की उम्मीद

इसके लिए विगत 15 व 22 फवरी को प्रांतव्यापी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर ध्यानाकर्षण किया गया था। सरकार से अपेक्षा है कि रोके गये डीए डीआर देय एरियर सहित समस्त स्वत्वों के भुगतान का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सभी का घरेलू बजट गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार के 02 मार्च को बजट से क्या निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई हैं।

इनका कहना है...

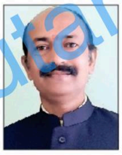

राज्य सरकार हमेशा से कर्मचारियों की हितैषी रही है। कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही। बजट में कर्मचारियों को सौगात मिलने की उम्मीद है।

हेमंत श्रीवास्तव, महामंत्री, राज्य कर्मचारी संघ

प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना जैसे संकटकाल में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। बजट में भी कर्मचारियों को सरकार राहत देगी।

मुरारीलाल सोनी, मजदूर नेता,

कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर ही पिछले दिनों आंदोलन किया गया था। अब उम्मीद है कि बजट में समस्त स्वत्वों के भुगतान का प्रावधान होगा।

प्रमोद तिवारी, प्रांताध्यक्ष, जागरूक अधिकारी कर्मचारी समिति

राज्य सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित मांगों का भुगतान शीघ्र करना चाहिए। बजट से कर्मचारी आशा लगाकर बैठे हैं, अन्यथा बड़ा विरोध होगा।

उदित भदौरिया, संयोजक, जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ

Badri Gautam

कैग के खुलासे के 2 साल बाद हो रही ढुंढ़ाई शौचालय विहीन स्कूलों की

राज्य शिक्षा केंद्र ने 41 जिलों के कलेक्टर पत्र लिखकर मांगी जानकारी

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9893231237

दो साल पहले वर्ष 2019 में कैग की रिपोर्ट में बताया गया था कि 21,022 स्कूलों शौचालय नहीं हैं और हैं भी तो उपयोग लायक नहीं है। प्रदेश में 2014-15 में स्वच्छ विद्यालय योजना के तहत स्कूलों में शौचालय स्वीकृत किए गए थे। अब लगभग 2 साल बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग की नींद खुली हैं और विभाग ने इसको लेकर जिलों से जानकारी जुटाना शुरू किया है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने 41 जिलों के कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा गया है कि पीएसयू द्वारा स्वीकृत एवं निर्मित शौचालयों का विवरण एवं स्थिति की जानकारी के लिए गूगल शीट संलग्न कर भेजी गई है। शौचालयों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन एवं उनकी क्रियाशीलता की जानकारी मांगी गई है। पत्र के साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र ने जिलों को 2014-15 में स्वीकृत शौचालयों की सूची भी भेजी है। सूची के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2014-15 में 21 हजार 22 शौचालय स्वीकृत किए गए थे।

इन जिलों के कलेक्टर से मांगी जानकारी

अलीराजपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, धार, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच सहित 41 जिले शामिल हैं। इनका कहना है स्कूलों की सुविधाएं व अन्य जानकारी मंगाना यह एक रूटीन प्रक्रिया है। सभी स्कूलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं।

Badri Gautam

कॉलेज में छात्राओं को बैंकिंग परीक्षा की करवाई तैयारी

संत हिरदाराम कॉलेज में कोचिंग क्लास आयोजित

पीपुल्स संवाददाता ● संत नगर

मो.नं. 8602467816

Badri Gautam

संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में स्नातक के विद्यार्थियों को बैंकिंग में कॅरियर बनाने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु दो माह की कोचिंग कक्षाएं आयोजित हुईं।

जानकारी के अनुसार इन कोचिंग कक्षाओं में छात्राओं को परीक्षाओं के नए प्रारूप के अनुसार नियमित सिलेबस पढ़ाया गया। तुलनात्मक अध्ययन, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स पर प्रश्नोत्तर, प्रैक्टिस तथा मौखिक टेस्ट के जरिए छात्राओं को प्रशिक्षित किया। प्राचार्य डॉ. डालिमा पारवानी ने कहा कि छात्राओं में इससे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आत्मविश्वास जगेगा। यह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावकारी होगा। इसमें करीब 100 छात्राएं शामिल हुईं।

बच्चों को स्कूल के लिए बुलाने हर रोज घोड़े पर निकलते है हरनाम

कोरोना के दौर में बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की कवायद ला रही रंग

सुरेश एस डुग्गर ● जम्मू
मो. नं. 9613565656

पीपुल्स समाचार स्पेशल

आपने न ही ऐसा कहीं देखा होगा और न ही सुना होगा कि बच्चों को सरकारी स्कूल तक लाने की खातिर एक अध्यापक घोड़े की सवारी कर, दुर्गम इलाकों में आतंकी खतरे के बीच शिक्षा की लौ जगाने का प्रयास कर रहा हो।

बच्चों को स्कूल भेजने के लिए घोड़े पर सवार होकर परिजनों से अपील करते हरनाम।

दरअसल, लॉकडाउन के बाद राजौरी का पद्दर स्थित मिडिल स्कूल खुल तो गया था, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे। इस स्कूल में 10 किमी के क्षेत्र से बच्चे शिक्षा लेने आते हैं। बच्चों के साथ अध्यापकों को भी करीब 5 किमी पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। लॉकडाउन से पहले यहां 50 बच्चे पढ़ते थे, अब इसके आधे ही आ रहे हैं।

लॉकडाउन के बाद कम हो गई थी छात्रों की संख्या

अध्यापक हरनाम सिंह ने बताया, लॉकडाउन के बाद जैसे ही स्कूल खुले, विद्यार्थियों की संख्या काफी कम हो गई। कई बार संदेश भेजा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब उन्होंने ठाना कुछ भी हो बच्चों को फिर से स्कूल लाना है। गांव के एक व्यक्ति के पास घोड़ा था, जिसे मांगने पर उन्हें दे दिया गया। इसके बाद छोटा लाउड स्पीकर लेकर बच्चों को स्कूल तक लाने की कवायद में जुट गए। और उनकी ये कोशिश रंग भी ला रही है।

सुबह 6 बजते ही थाम लेते हैं घोड़े की लगाम

हरनाम सिंह सुबह 6 बजे अपने घर से घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं और उसके बाद वह 10 बजे अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। हरनाम सिंह ने बताया, हर रोज 10 से 12 किमी का सफर घोड़े पर हो जाता है। लोग जागरूक हो रहे हैं और स्कूल आकर बच्चों के नाम लिखवा रहे हैं, ताकि नई कक्षाओं में उन्हें दाखिला मिल सके। इसके साथ-साथ जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, वह भी स्कूल आना शुरू हो चुके है। हरनाम बच्चों को पढ़ाने के लिए नए-नए प्रयोग भी करते रहते हैं।

केंद्रीय मंत्रालय भी कर चुका है सम्मानित

शिक्षा को लेकर जुनूनी अध्यापक हरनाम सिंह को 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और इनोवेटर के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2018 और 2019 में जम्मू के स्कूल शिक्षा निदेशक भी उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में सम्मानित कर चुके हैं।

Badri Gautam

आंसरसीट बदलने से 12वीं की छात्रा फेल, जांच के बाद विषय में मिले 64 नंबर, मूल्यांकन से जुड़े तीन शिक्षकों पर लगा तीन साल का बैन

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों का बड़ा मामला सामने आया है। वर्ष 2019-20 की परीक्षा में 12वीं की कॉमर्स की छात्रा की आंसरशीट बदलकर फेल कर दिया गया। जांच के बाद मामला सही पाए जाने पर एमपी बोर्ड ने तीन शिक्षकों को तीन साल के लिए डिबार (प्रतिबंधित) कर दिया है। यह तीनों शिक्षक अब तीन साल तक किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं बन सकेंगे।

दरअसल, वर्ष 2020 की 12वीं बोर्ड परीक्षा में कॉमर्स संकाय की छात्रा यामिनी शर्मा को एक विषय में केवल 20 अंक मिले थे, जिससे एक विषय में पूरक आ गया। छात्रा इससे संतुष्ट नहीं थी। उसने बोर्ड में पुनर्गणना और आंसरशीट देखने के लिए आवेदन किया तो देखकर हैरान हो गई। उसकी कॉपी बदली हुई थी और रोल नंबर में छेड़छाड़ की गई थी। यहां तक की कापी में लिखावट, परीक्षा कक्ष क्रमांक से लेकर परीक्षा की तारीख तक गलत थी। जांच करने के बाद मंडल ने छात्रा को उस विषय में 64 अंक मिले हैं। छात्रा द्वितीय श्रेणी से पास भी हुई। इस मामले में मंडल ने यह निर्देश जारी किए हैं कि मूल्यांकन संबंधी कार्य अत्यंत संवेदीनशील प्रकृति का है। इससे सीधे तौर पर विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा रहता है। कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए तीनों मूल्यांकनकर्ताओं को परीक्षा संबंधी कार्य से प्रतिबंधित किया जाता है।

- रोल नंबर में भी छेड़छाड़ की गई जांच करने के बाद छात्रा हुई उत्तीर्ण माशिमं ने शिक्षकों पर की कार्रवाई

इन तीनों शिक्षक पर लगाया गया प्रतिबंध

एमपी बोर्ड ने परीक्षक, उपमुख्य परीक्षक और मुख्य परीक्षक को परीक्षा वर्ष 2021, 2022 व 2023 के लिए मंडल द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी पारिश्रमिक संबंधी कार्यों से प्रतिबंधित किया गया। तीनों उज्जैन जिले के शिक्षक हैं, इनमें प्राइवेट संतमीर कान्वेंट स्कूल नयापुरा की शिक्षक शोभा सक्सेना, शासकीय उमावि महाराजवाड़ा के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक डीएस कनेल, शासकीय हाईस्कूल बघेरा के प्राचार्य राज कुमार पोरवाल को प्रतिबंधित किया गया है।

प्रदेश में पहली बार अब दूसरे स्कूलों में जाकर प्रायोगिक परीक्षा दे सकेंगे छात्र

- अब तक अपने ही स्कूलों में देने का था चलन, निजी स्कूलों की आपत्ति, कहा- प्रयोग कोरोना के बीच ही क्यों?

प्रदेश में पहली बार दूसरे स्कूलों में जाकर छात्र-छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा देंगे। इससे जुड़ा हुआ एक आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जारी हुआ है, जिसे लेकर निजी स्कूलों का विरोध भी शुरू हो चुका है। बता दें कि अब तक के इतिहास में जो छात्र जिस स्कूल में पढ़ता था, उसकी प्रायोगिक परीक्षा भी उसी स्कूल में होती थी। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि सारे नए प्रयोग कोरोना महामारी के बीच ही क्यों किए जा रहे हैं? इस निर्णय से लैबों की संख्या कम हो जाएगी, वहीं कुछ लैबों पर ज्यादा भार आ जाएगा। एक दिन में 50 से अधिक विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जा सकती हैं।

9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स का शेड्यूल जारी

9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स का शेड्यूल माशिमं के सचिव ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 15 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच होंगी। जबकि इसके लिए मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति का कार्य 5 अप्रैल से शुरू होगा। हालांकि अभी प्रैक्टिकल का टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। इसे पांच अप्रैल या इससे पहले जारी किया जाएगा।

इस तिथि से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं

10वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होंगी। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा 1 घंटे पहले सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 11 बजे तक चलेगी।

इस नियम को वापस ले माशिमं

हम माध्यमिक शिक्षा मंडल से अपील करते है कि इस नियम को वापस ले। इस कोरोना काल में नए नए प्रयोग न करें, यह छात्र हित में नहीं है।

दीपक राजपूत, संस्थापक सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स

Badri Gautam

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वॉयरनमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट में खुलासा

25 करोड़ बच्चों का छूटा स्कूल 37.5 करोड़ की सेहत प्रभावित

एजेंसी ▸▸| नई दिल्ली

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वॉयरनमेंट (सीएसई) की स्टेट ऑफ इंडिया इन्वॉयरमेंट रिपोर्ट के 2021 अनुसार, कोरोना महामारी के कारण देश भर में 37.5 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य और आर्थिक हालात पर स्थायी असर पड़ा है।

सीएसई की महानिदेशक डॉ. सुनीता नारायण ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया, नवजात से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें ज्यादा हुई हैं। इसमें बच्चों का कम वजन, उम्र के अनुसार, शारीरिक विकास न होना और मृत्यु दर में बढ़ोतरी की आशंका है। बच्चों की खराब सेहत के कारण शिक्षा और कार्य क्षेत्र में भी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन जारी की गई इस रिपोर्ट को दुनियाभर के साथ पर्यावरण और अन्य विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है।

खास बातें

- कोरोनाकाल में बच्चों के स्वास्थ्य और आर्थिक हालात पर पड़ा स्थायी असर
- महामारी के कारण अतिरिक्त 115 करोड़ लोग आए अत्यंत गरीबी के दायरे में
- इस रिपोर्ट को

महामारी से 50 करोड़ बच्चों का स्कूल छूटा

महामारी के कारण दुनिया भर में 50 करोड़ बच्चों का स्कूल छूट गया। इसमें से 50 फीसदी से ज्यादा बच्चे भारत में है। सुनीता नारायण ने कहा, महामारी के कारण अतिरिक्त 115 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी के दायरे में आ चुके हैं। इसमें से अधिकतर दक्षिण एशिया में रहते हैं।

192 देशों में भारत 117वें स्थान पर

सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में भारत दुनिया भर के 192 देशों की सूची में 117वें स्थान पर है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे हैं। सतत विकास लक्ष्यों को पाने में 5 राज्य केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना बेहतर है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और यूपी सबसे पीछे हैं।

बढ़ता प्रदूषण सेहत के लिए और घातक

बीमारी, कुपोषण, अत्यंत गरीबी जैसी समस्याओं से मुश्किल होगी। हवा और पानी में प्रदूषण स्तर बढ़ने का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लॉकडाउन में भी नदियों के प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई है। सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए साफ पानी के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करना होगा।

महाराष्ट्र का तारापुर प्रदूषित क्लस्टर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, देश के 88 प्रमुख औद्योगिक कलस्टर में से 35 में समग्र रूप से पर्यावरण में गिरावट आई है। 33 स्थानों पर हवा की गुणवत्ता खराब, 45 स्थानों पर साल भर दूषित पानी जबकि 17 स्थानों पर भूमि प्रदूषण अधिक था। महाराष्ट्र का तारापुर सबसे प्रदूषित क्लस्टर था।

2025 तक स्क्रैपेज नीति की जरूरत

रिपोर्ट के अनुसार, भारत को वर्ष 2025 तक वाहनों के स्क्रैपेज के लिए नीति की जरूरत होगी। देश में दो करोड़ वाहन ऐसे हैं जिनका जीवन अंत की ओर है। अगर सही समय पर इनका निस्तारण नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे। भारत में वर्ष 2019 में 16.70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं।

889 जीवों पर मंडरा रहा खतरा

भारत में 430 पौधे जिसमें 95 फीसदी फूल और खाद्य पदार्थ वाले हैं। वे खात्मे की कगार पर हैं। रीढ़ और रीढ़ विहीन 889 जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण से जुड़े आपराधिक मामले बढ़े हैं। 2019 में 24,671 केस दर्ज हुए थे जबकि 49,877 मामले लंबित हैं।

Badri Gautam

कोचिंग में बंधक बनाकर संचालक ने युवती के साथ की छेड़छाड़

भोपाल(आरएनएन)। पिपलानी थाना क्षेत्र में एक कोचिंग संचालक ने शनिवार दोपहर युवती को कोचिंग संस्थान में ही बंधक बनाकर अश्लील हरकतें की। पीड़ित युवती ने कॉल कर अपने भाई को बुला लिया। कोचिंग संचालक ने समझाइश देने पहुंचे युवती के भाई के साथ भी बुरी तरह मारपीट कर दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में रहने वाली 24 वर्षीय युवती एक लर्नर कोचिंग में टायपिंग सीखती थी। कोचिंग का संचालक योगेश खरे उसे आए दिन परेशान करता था। इसी कारण से युवती ने कोचिंग छोड़ दी थी। इसके बाद योगेश खरे बार-बार कॉल कर युवती को परेशान करने लगा। तंग आकर युवती ने संचालक योगेश खरे का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद भी आरोपी योगेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। योगेश ने युवती की सहेली को कॉल कर उसे कोचिंग जरूरी बात करने के लिए बुलवा लिया।

विरोध करने पर भाई को पीटा

शनिवार 27 फरवरी की दोपहर करीब ढाई बजे युवती सहेली के साथ कोचिंग पहुंची तो योगेश खरे ने बात करने के बहाने सहेली को कमरे से बाहर कर दिया। सहेली के कमरे से बाहर जाते ही योगेश खरे ने दरवाजा भीतर से बंद कर युवती को बंधक बना लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाते हुए किसी तरह युवती कमरे से बाहर निकली। पीड़ित युवती ने घटना की जानकारी अपने भाई को दी।

भाई कोचिंग पहुंचा। उसने कोचिंग संचालक को समझाइश देने का प्रयास किया। लेकिन गुस्साए योगेश ने युवती के भाई के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद अपने भाई के साथ थाने पहुंची युवती ने आरोपी योगेश खरे के खिलाफ बंधक बनाकर छेड़छाड़ करने व मारपीट करने का प्रकरण दर्ज किया है।

Badri Gautam

बच्चों की सुरक्षा, अपराध से बचाने के रक्षा समिति सदस्यों को बताए तरीके

भोपाल। बच्चों की सुरक्षा और उनसे होने वाले अपराधों की रोकथाम के तरीके बताने नगर सुरक्षा

कार्यशाला

समितियों को प्रशिक्षण दिया। चाइल्ड की लाइन डायरेक्टर अर्चना सहाय, सेफ सिटी पहल से राखी रघुवंशी, लक्ष्मी कुशवाहा, विजय यादव, करुणा गवई आदि ने प्रशिक्षण दिया। कोतवाली थाना प्रभारी अजय मिश्रा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हम सबकी पहली जिम्मेदारी है? कोई भी बच्चा किसी तरह के संकट में दिखे तो तत्काल पुलिस अथवा चाइल्ड लाइन को सूचित करें। प्रशिक्षण में सदस्यों ने सवाल भी किए, जिनके जवाब दिए गए।

Badri Gautam

फिर बढ़ी तिथि, अब 21 को होगी प्रवेश परीक्षा

उत्कृष्ट व मॉडल विद्यालयों की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन तिथि भी बढ़ाई

जागरण, रीवा। उत्कृष्ट विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक 1 तथा जिले के अन्य मॉडल स्कूल की कक्षा 9वीं के लिए प्रवेश परीक्षा अब 14 की जगह 21 मार्च को होगी। इस बाबत स्कूल शिक्षा विभाग ने सूचना जारी कर दी है। इसके पूर्व यह परीक्षा कराने 28 फरवरी तिथि निर्धारित रही परंतु नियत तिथि तक छात्रों के पर्याप्त आवेदन नहीं प्राप्त हुए। इस बार भी इन्हीं कारणों से यह स्थिति बनी। लिहाजा विभाग ने ऑनलाइन फार्म भरने के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि सत्र 2021-22 में उत्कृष्ट विद्यालय मार्तण्ड 1 की कक्षा 9वीं की 240 में प्रवेश होना है। वहीं, जिले की 8 मॉडल स्कूल की कक्षा 9वीं की 90-90 सीट में छात्रों को प्रवेश दिया जाना है।

इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए पिछले एक महीने से ऑनलाइन फार्म प्राप्त किये जा रहे हैं लेकिन इस बार अब तक सीट भरने के लिहाज से छात्रों ने आवेदन करने में रूचि नहीं दिखाई, जिसके चलते आवेदन फार्म भरने की तिथि में इजाफा किया गया है। वहीं, छात्र संख्या स्पष्ट न होने के कारण अभी केंद्र भी तय नहीं किए गए हैं। अब फार्म भरने का समय समाप्त होने के बाद परीक्षा केंद्रों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Badri Gautam

गणित और विज्ञान के होंगे 20-20 प्रश्न

इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न छात्रों से पूछ जायेंगे। इनमें 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। ऐसे ही 15 प्रश्न पर्यावरण के, 15 प्रश्न हिंदी, 15 अंग्रेजी और विज्ञान-गणित के 20-20 प्रश्नों समाहित होंगे। दो घंटे की परीक्षा में छात्रों को एक प्रश्न पत्र में समाहित उक्त 100 प्रश्नों को हल करना होगा। यह प्रवेश परीक्षा कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित कराई जायेगी। जबकि परीक्षा के समन्वय का कार्य सचिव व जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा किया जायेगा।

भुगतान में नहीं होगा विलंब

अब सभी पेंशन प्रकरण ऑनलाइन तैयार होंगे

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के संदर्भ में अगले माह में सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों को ऑनलाइन तैयार कर लिया जाएगा ताकि पेंशन भुगतान में एक भी दिन का विलंब नहीं हो। पेंशन प्रकरणों के सबंध में आने वाली कठिनाईयों के लिए संभागीय पेंशन अधिकारी व कोषालय से सम्पर्क किया जा सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये तीन दिवसीय प्रशिक्षण के समापन सत्र में इस विषय पर चर्चा हुई।

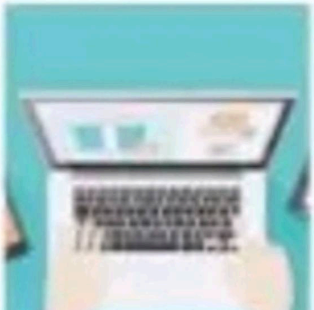

Badri Gautam

अफसरों की समस्याओं का किया निराकरण

वल्लभ कोषालय भोपाल द्वारा वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के अंतर्गत पेंशन प्रकरणों में आ रही विभिन्न स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। पेंशन एवं ईएसएस माडयूल के अंतर्गत कठिनाइयों के त्वरित निराकरण के लिए वित्तीय सलाहकार तथा आहरण संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित कर शंकाओं का समाधान भी किया गया।

चुनावी ड्यूटी पर तैनात हर कर्मी को लगेगा टीका

नई दिल्ली, जेएनएन। पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी को चुनावी तारीखों का एलान किया। 27 मार्च से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।दो मई को मतों की गिनती के बाद स्पष्ट होगा कि साल 2021 में होने वाले इन पहले चुनावों में बाजी किसके हाथ लगती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कई अहम जानकारियां दी। देश में दोबारा तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच यह स्पष्ट किया गया कि चुनावी ड्यटी पर लगे हर कर्मचारी का कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात हर कर्मी को टीकाकरण के मकसद से अग्रिम मोर्चा का कार्यकर्ता घोषित किया है। कोरोना दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मतदान के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्हें अग्रिम मोर्चा कार्यकर्ता घोषित किया

Badri Gautam

अंततः रमाशंकर को मिला गढ़ी हायर सेकेण्डरी का प्रभार

जागरण, रीवा। अंततः गढ़ी हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्राचार्य का प्रभार जूनियर की जगह सीनियर को दे दिया गया। व्याख्याता रमाशंकर को गढ़ी प्राचार्य बनाए जाने का जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है।

ज्ञात हो कि गढ़ी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ वरिष्ठ व्याख्याता रमाशंकर सिंह ने नियम विरुद्ध दिए गए प्रभार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत भी की थी। रमाशंकर सिंह ने डीईओ को लिखे पत्र में कहा था कि वह वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर शासकीय उमावि गढ़ी में पदस्थ हैं। उन्होंने प्रभारी प्राचार्य के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्रभार नहीं दिया गया। प्राचार्य ने पत्र लिखकर दोबारा प्रभार मांगा है। यहां जूनियर को प्राचार्य बनाकर बैठा दिया गया है। वहीं रमाशंकर सिंह उनसे सीनियर हैं। उनके पत्राचार और विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी डॉ आरएन पटेल ने आदेश जारी कर रमाशंकर सिंह को गढ़ी विद्यालय का प्रभारी प्राचार्य नियुक्ति कर दिया है। उनके प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने पर रघुवंश तिवारी, केडी मिश्रा, देवराज वर्मा, उमाकांत मिश्रा आदि ने प्राचार्य को बधाई दी है।

कई स्कूलों में चल रही मनमानी

ऐसा कई स्कूलों में है जहां जूनियर ही प्राचार्य की कुर्सी सम्हाल रहे हैं। सीनियर को दरकिनार कर दिया गया है। स्कूल की व्यवस्था और जिम्मेदारियों से भी वरिष्ठ शिक्षक पल्ला झाड़ रहे हैं। यही वजह है कि शासकीय विद्यालयों की दुर्गति हो गई है। कई सीनियर शिक्षक प्राचार्य की जिम्मेदारी सिर्फ काम के डर से नहीं लेते। शासकीय वेतन पर मजे जरूर कर रहे हैं।

Badri Gautam

हर्राखेड़ा हायर सेकंडरी स्कूल में लगा दिव्यांगजनों का परीक्षण शिविर

कैंप

भोपाल। जिले की बैरसिया तहसील के ग्राम ललरिया में एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदान करने एवं एडिप योजना अंतर्गत दिव्यांगजनों का चिन्हांकन उपरांत कृत्रिम अंग सहायक उपकरण देने के लिए शनिवार को शिविर आयोजित किया गया। इसमें डॉ. बीके दुबे, डॉ. निशा मिश्रा, डॉ. आरके बैरागी, डॉ. तनमय शाह एवं डॉ. एचएन साहू उपस्थित थे। शिविर में कुल 840 से अधिक दिव्यांगजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

Badri Gautam

अब वॉट्सऐप पर लिंक शेयर नहीं करेगा SC

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक वॉट्सऐप ग्रुप पर शेयर नहीं करेगा। न्यायालय रजिस्ट्री ने शनिवार को यह जानकारी दी। रजिस्ट्री ने बताया कि अब वॉट्सऐप के बजाय सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल सुनवाई के लिए लिंक संबद्ध वकील एवं पक्षकार के रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पर शेयर किया जाएगा। यह कदम सरकार के नए आईटी नियमों के आने के बाद उठाया गया है।

Badri Gautam

गलत आदेश जारी करने का था दबाव, नहीं किए तो जेडी का खत्म कर दिए प्रभार

जेडी लोक शिक्षण का प्रभार नीरव दीक्षित से छिना, शहडोल के सहदेव सिंह को मिला

जागरण, रीवा

जेडी लोक शिक्षण संचालनालय का प्रभार सतना डाइट प्राचार्य नीरव दीक्षित को मिला था। इन पर लगातार रिटायर्ड जेडी रुके हुए भुगतान की फाइल क्लियर करने का दबाव डलवा रहे थे। दबाव पर काम न करने पर प्रभार ही बदल दिया गया। अब जेडी का प्रभार शहडोल के संयुक्त संचालक सम्हालेंगे।

ज्ञात हो कि जेडी लोक शिक्षण संचालनालय अंजनी त्रिपाठी के रिटायर होने के बाद से कुर्सी प्रभार पर ही थी। श्री त्रिपाठी के बाद पीजीबीटी प्राचार्य प्रफुल्ल शुक्ला प्रभारी रहे। वह रिटायर हुए तो कुर्सी खाली हो गई। उसकी जगह पर सतना डाइट प्राचार्य नीरव दीक्षित को प्रभारी बना दिया गया। उनके कुर्सी पर बैठते ही कईयों की फाइलें खुल गईं। रिटायर्ड हो चुके जेडी के कारनामों की जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। यही वजह है कि प्रभारी को हटाने और उन दबाव बनाने के लिए रिटायर हो चुके अधिकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रभारी जेडी नीरव दीक्षित ने भोपाल के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि गलत आदेश नहीं करेंगे, चाहे तो प्रभार से हटा दें। और हुआ वही। आयुक्त जश्री कियावत ने आदेश जारी कर नीरव दीक्षित का प्रभार खत्म कर शहडोल जेडी सहदेव सिंह मरावी को जिम्मेदारी सौंप दी है।

इनकी एनओसी पर लगी आपत्ति

एनएस तिवारी वर्ष 2011, 12 में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रहे। यह भी औपचारिकेत्तर गुरुजी के एरियर्स घोटाले में फंसे थे। इन पर करीब 73 लाख रुपए की रिकवरी निकली थी। हालांकि इनकी वसूली पर कोर्ट से राहत मिल गई थी। कोर्ट ने प्रकरण खत्म होने तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। श्री तिवारी जेडी भी रहे। यह अब रिटायर हो चुके हैं। ताज्जुब तो यह है कि इन्हें जो विभाग से एनओसी जारी की गई है। उसमें न्यायालयीन प्रकरण को नजर अंदाज किया गया है। इस पर जेडी ने आपत्ति दर्ज करते हुए आयुक्त रीवा संभाग रीवा को पत्र भी लिखा है। इसमें साफ कहा गया है कि एसएन तिवारी वर्ष 31 जनवरी 2018 को जेडी के पद से रिटायर हुए। रिटायमेंट के बाद विभागीय जांच न्यायालयीन प्रकरण डब्लूपी क्रमाक 2597/2015 लंबित रहने के बावजूद पूर्व जेडी अंजनी त्रिपाठी ने एनओसी जारी कर दी। एनओसी में मांग, जांच और घटना की जानकारी निरंक कर भेज दी गई। जबकि नोटसीट में हाईकोर्ट की रिट यचिका के विचाराधीन रहने का जिक्र था। कमिश्नर रीवा संभाग रीवा से तत्कालीन जेडी के खिलाफ कार्रवाई करने का लेख भी किया गया है।

क्लेम भी हो गए क्लियर

दूसरा मामला सहायक संचालक जेडी कार्यालय में पदस्थ रहे धीरेन्द्र सिंह का है। वह पहले सितलहा स्कूल में प्राचार्य थे। उन्होंने औपचारिकेत्तर गुरुजी और व्यापमं परीक्षा में अनुत्तीर्ण गुरुजी को करीब 75 लाख का एरियर्स भुगतान कर दिया था। इनके खिलाफ भी 75 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई है। इनकी भी एनओसी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी कर दी गई। इनके सारे क्लेम भी क्लियर कर दिए गए। इन्हें भी गलत तरीके से एनओसी दी गई है।

Badri Gautam

उच्च शिक्षा मंत्री के स्वागत में सजे विवि और महाविद्यालय

डॉ मोहन यादव आज रीवा प्रवास पर, नवीन भवनों का करेंगे लोकार्पण

जागरण, रीवा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को रीवा प्रवास पर रहेंगे। रीवा आगमन होने पर पहले डॉ यादव पहले सुबह 11 बजे शासकीय विधि महाविद्यालय जायेंगे, जहां करीब साढ़े पांच करोड़ की लागत से बने नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। हालांकि इस भवन में काफी तकनीकी गड़बड़ी रही, जिसमें से गड़बड़ी पीआईयू ने छुपाने के वास्ते सुधार ली है। बहरहाल, विधि महाविद्यालय के कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री के अलावा रीवा सांसद जर्नादन मिश्र, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहेंगे। इसके उपरांत उच्च शिक्षा मंत्री दोपहर 12 बजे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जायेंगे, जहां उनके द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के प्रथम तल विस्तार व पार्किंग शेड का लोकार्पण किया जायेगा। इसके उपरांत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के स्वागत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कार्यपरिषद सदस्य अजय सिंह, व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री के आगमन को लेकर विधि महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में दिनभर तैयारी चलती रही। विश्वविद्यालय परिसर को पूरी तरह सेनेटाइज करने में कर्मचारी जुटे रहे। उच्च शिक्षा मंत्री दोपहर डेढ़ बजे मनगवां रवाना होंगे, जहां शासकीय महाविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण उनके द्वारा किया जायेगा। फिर उच्च शिक्षा मंत्री दोपहर 3 बजे मनगवां से वापस रीवा आयेंगे। रीवा राजनिवास में ठहरकर शाम साढ़े 4 बजे उच्च शिक्षा मंत्री सतना अमरपाटन के लिए प्रस्थान करेंगे।

Badri Gautam

पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिया ज्ञापन

सतना। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। चित्रकूट प्रवास पर आए उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव से विश्वविद्यालय के संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के संयोजक गुरू प्रकाश शुक्ला के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई।

Badri Gautam

परीक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार कर रहे कर्मचारी

भास्कर न्यूज. **सतना**

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय से भेजे गए परीक्षा केन्द्रों के प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद कार्यालय के कर्मचारी नए सिरे से परीक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हुए हैं। पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल को 105 परीक्षा केन्द्रों की सूची भेजी गई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अब ऐसे स्कूलों का चयन परीक्षा केन्द्र के लिए किया जा रहा है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की गाइड लाइन के अनुसार हों। परीक्षा केन्द्र निरस्त होने पर इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी परीक्षा केन्द्र छात्रों की स्कूल से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर न हो।

7 दिन में भेजना है प्रस्ताव • जिला शिक्षा कार्यालय को परीक्षा केन्द्रों की सूची तैयार कर इसे माध्यमिक शिक्षा मंडल को 7 दिन के अंदर भेजना है। परीक्षाओं के महज 60 दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा केन्द्र तय नहीं हो सके हैं। डीईओ ऑफिस से जुड़े जानकार बताते हैं कि पूर्व में कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इनकी संख्या घटाई जा रही है। बताया गया कि अधिकांशतः वही परीक्षा केन्द्र होंगे जो बीते सत्रों में बनाए गए थे।

Badri Gautam

महिला एवं बाल विकास विभाग के कारनामों की खुल रहीं परतें

स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों के नाम पर हो चुका है 128 लाख का घोटाला

● राजीव अग्रवाल

ग्वालियर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक नहीं कई तरह के घोटाले किए गए हैं। हाल ही में जहां लॉकडाउन में पोषण आहार वितरण के नाम पर लगभग 12 करोड़ रुपए के भुगतान से विभाग के कर्ता-धर्ता सवालों के घेरे में हैं। वहीं पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद प्रदेश के चार जिलों में स्कूल न जाने वाली बच्चियों को टेकहोम राशन वितरण के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ था, जिसकी जांच आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है। इसमें ग्वालियर में भी 128. 54 लाख का घोटाला सामने आया था। इससे स्पष्ट है कि ग्वालियर में बैठे विभाग के अधिकारी सिर्फ कागजों पर पोषण आहार वितरण दिखाकर ठेकेदारों और अपनी बल्ले-बल्ले कर रहे हैं।

ईओडब्ल्यू कर रहा है जांच

यहां बता दें कि ग्वालियर में चार स्व सहायता समूह को पोषण आहार वितरण का एक तरफा ठेका देकर विभाग के अधिकारियों की गर्दन बुरी तरह फंसी हुई है। इसे लेकर भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी भी अब चौकन्ना हो गए हैं कि आखिर प्रदेश शासन के नाम पर इस तरह की गड़बड़ी किसने और कैसे की। वहीं दूसरी ओर स्कूल नहीं जाने वाली किशोरवय बच्चियों (11 से 14 वर्ष) को टेकहोम राशन का वितरण किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसी) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के सामने विदिशा दौरे के दौरान बड़ा घोटाला सामने आया था। जिस पर उन्होंने ग्वालियर, बेतूल, डिंडोरी और सिंगरौली में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत आकडों की जांच स्कूली शिक्षा विभाग से करवाई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दो लाख आठ हजार पांच सौ पचपन बच्चियों को स्कूल न जाना दिखाते हुए एक लाख 71 हजार 365 बच्चियों को टेकहोम राशन वितरण करना बताया।

स्कूली शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में यह आंकड़ा एकदम गलत पाया गया, क्योंकि उनकी रिपोर्ट में मात्र 8680 बच्चियों ने स्कूल छोड़ा था। इस तरह विभाग द्वारा प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपए का टेकहोम राशन वितरण दर्शाया गया। *(शेष पृष्ठ सात पर...)*

इनका कहना है

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल न जाने वाली बच्चियों के टेकहोम राशन के फर्जीवाड़े में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया था। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी लेकर आपसे बात करूंगा।

प्रियंक कानूनगो
अध्यक्ष राष्ट्रीय, बाल संरक्षण आयोग

बाल संरक्षण आयोग और महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए शिकायती पत्रों के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के टेकहोम राशन मामले की जांच चल रही है। जांचोपरांत ही कार्रवाई होगी।

अजय शर्मा
विशेष महानिदेशक ईओडब्ल्यू भोपाल

Badri Gautam

माशिमं से क्यों हुई जुलानिया की विदाई?

प्रशासनिक संवाददाता ■ भोपाल

अंततः मुख्यमंत्री की नाराजगी, स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री से अनबन और विभाग की प्रमुख सचिव की पांच चिट्ठियों का जवाब नहीं देना माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के वरिष्ठ अधिकारी राधेश्याम जुलानिया को भारी पड़ गया और उनकी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। अब उनकी नई पदस्थापना मंत्रालय में ओएसडी के रुप में की गई है। साथ ही ओएसडी के पद को राजस्व मंडल अध्यक्ष के समकक्ष घोषित किया गया। जुलानिया की जगह रश्मि अरुण शमी को ही माशिमं अध्यक्ष पद का प्रभार दे दिया गया है। जुलानिया को ओएसडी बनाने से एक बात तो साफ हो चुकी है कि सेवानिवृत्ति तक उनके पास अब कोई काम नहीं रहेगा। वह सितंबर 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

मंत्री भी थे नाराज

उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया और विभागीय प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी के साथ पटरी नहीं बैठ रही थी। बताया जा रहा है कि विभागीय मंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव द्वारा पांच पत्र परीक्षा की तारीखों व तैयारियों को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया को लिखे गए थे। इसी बात को दोनों नौकरशाहों के बीच खींचतान के चलते न केवल विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा था, बल्कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं की प्रणाली में बदलाव को लेकर भी बखेड़ा खड़ा हो गया था। जिसके बाद विभागीय मंत्री ने जुलानिया से जबाव तलब किया था। लेकिन अपने अक्खड़ स्वाभाव के लिए जाने जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी को विभागीय मंत्री की सलाह भी नागवार गुजरी, जिससे खींचतान और बढ़ गई। बाद में सारे घटनाक्रम की जानकारी विभागीय मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी थी।

कहां से शुरु हुआ विवाद?

दरअसल स्कूली शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया के मध्य विवाद की शुरुआत तब हुई, जब परीक्षा कराने और समय

क्या करना चाहते थे जुलानिया?

जुलानिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र प्रणाली (ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न) लाना चाहते थे। इससे ओएमआर शीट (ऑप्टिकल मार्क रीडर) से परीक्षा होती। यू-ट्यूब चैनल से पढ़ाने की तैयारी थी। निजी स्कूलों के कुछ लोग ज्ञापन लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष से मिले थे कि प्रणाली अभी न बदली जाए। जुलानिया ने इस ज्ञापन को उनके सामने ही फाड़ दिया। उन्होंने सालों से चली आ रही निजी काउंसलिंग की व्यवस्था को भी बंद करके सरकारी काउंसलिंग की व्यवस्था स्थापित कर दी थी। साथ ही कहा कि बोर्ड में बैठे लोग ही काउंसलिंग करेंगे। इससे सरकार नाखुश थी। क्योंकि काउंसलिंग की सालों से चली आ रही परंपरा बंद हो गई थी। साथ ही नए प्रणाली के लिए फिलहाल इस शिक्षण सत्र में समय नहीं बचा था।

तय करने के लिए रश्मि अरुण शमी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष को पहला पत्र 30 दिसंबर 2020 को लिखा। इसका जवाब नहीं मिला, तो फिर रश्मि अरुण शमी ने 8 जनवरी 2021, 15 जनवरी, 23 जनवरी और फिर 18 फरवरी को पत्र लिखा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इनमें से एक का भी जवाब माध्यमिक शिक्षा मंडल से नहीं आया।

इस वजह से परीक्षा के न प्रश्न पत्र बने और न ही कोई को कारगर कार्ययोजना तैयार हो सकी। ताजा स्थितियों में केन्द्रीय शिक्ष बोर्ड (सीबीएसई) परीक्षाओं के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा के टकराने की स्थितियां बन गईं। जुलानिया मई में परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे थे, जबकि शासन इससे पहले। जब इस बारे में स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री ने जुलानिया से पूछा, तो उन्होंने यह कह दिया कि मंत्री का इससे कोई लेना-देना नहीं है। परीक्षा केंद्रों को पिछले साल की तुलना में घटा दिया गया, जबकि कोरोना के समय में इसे बढ़ाना चाहिए था। ताकि बच्चों को दूर न जाना पड़े।

Badri Gautam

सहायक शिक्षक संवर्ग के वेतनमान की विसंगति दूर करें

भोपाल। मप्र शिक्षक कांग्रेस ने सहायक शिक्षक संवर्ग के वेतनमान की विसंगति दूर करने की मांग की है। उनकी मांग है कि सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता संवर्ग के वेतनमान एक जनवरी 1996 के पूर्व केंद्र सरकार के शिक्षक संवर्ग टीजीटी, पीजीटी के समान वेतनमान स्वीकृत थे। इस संबंध में शिक्षक कांग्रेस ने मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर वेतनमान की विसंगति को दूर करने की मांग की है। (नप्र)

Badri Gautam

गर्मी में बोर्ड परीक्षा कराने जैसे जुलानिया के फैसले से थे खफा

भोपाल (नवदुनिया स्टेट ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम आइएएस अधिकारी और मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से हटाए गए अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया लंबे समय से सरकार के निशाने पर थे। सरकार भीषण गर्मी (मई-जून) में हाई-हायर सेकंडरी परीक्षा कराने, कोरोना काल में परीक्षा पैटर्न बदलने और आउटसोर्स पर रखे काउंसलरों को परीक्षा के ठीक पहले हटाने जैसे फैसलों से खफा थी। इन फैसलों के चलते उनकी स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी से भी पटरी नहीं बैठ पा रही थी। हालांकि जुलानिया सभी आरोपों को सिरे से नकारते हैं। वे कहते हैं कि परीक्षा पैटर्न से लेकर मंडल में जो भी बदलाव हुए, वह सरकार की सहमति से हुए। क्योंकि बदलाव के समय कोई विरोध नहीं किया गया। उनसे चर्चा के अंश।

आरएस जुलानिया

सरकार खुश है या नहीं, मैं नहीं कह सकता

आप पर आरोप हैं कि मंत्री और शासन स्तर से पूछे जाने वाले सवालों, पांच पत्रों के जवाब नहीं दे रहे थे। क्या ये सही है?

● मंत्री ने कभी भी गैर जिम्मेदार नहीं कहा।

शासन स्तर से मना करने के बाद भी आपने माशिमं की व्यवस्थाएं बदल दीं। क्या ये सही है?

● स्कूल, छात्र और प्राचार्य बदलाव के पक्ष में थे। इसीलिए सरकार ने नए पैटर्न पर छमाही परीक्षा भी आयोजित की।

कोरोना काल में परीक्षा पैटर्न बदल दिया, जबकि शासन इसके लिए तैयार नहीं था। क्या ये सही है?

● सरकार खुश थी या नहीं, मैं नहीं कह सकता। निजी स्कूल एसोसिएशन इन सुधारों के पक्ष में था। एसोसिएशन से नया पैटर्न निरस्त करने के आदेश का विरोध करते हुए सरकार को लिखा है।

वर्तमान परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र बढ़ाने पर विचार चल रहा था और आपने कम कर दिए। क्या ये सही है?

● परीक्षा केंद्र छात्रों की संख्या और दूरी के आधार पर तय किए जाते हैं। बोर्ड ने वर्ष 2010 में परीक्षा केंद्रों के लिए दिशा-निर्देश और नियम बनाए हैं। उनका ही पालन किया गया है।

आपने आउटसोर्स पर काउंसलिंग करने वाले कर्मचारियों को हटाकर नियमित कर्मचारियों को बैठा दिया था। सरकार इससे भी खफा थी। क्या ये सही है?

● काउंसलिंग बाहरी लोगों को नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि परीक्षाओं के दौरान छात्रों की सहायता के लिए होती है। बोर्ड के पास बड़ी संख्या में व्यक्ति हैं, जो परामर्श के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

Badri Gautam

20 साल की नौकरी में 18 लाख वेतन, संपत्ति 3.50 करोड़ की

दबिश● मंदसौर में सोसायटी प्रबंधक के घर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई

मंदसौर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने शनिवार सुबह करीब छह बजे से गांव लदूसा में सहकारी सोसायटी धुंधड़का के प्रबंधक नंदकिशोर धाकड़ के घर कार्रवाई की। शाम तक चली कार्रवाई में लगभग 3.5 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति, तीन लाख रुपये, पांच हजार वर्गफीट में बना दो मंजिला आलीशान बंगला, तीन किलो चांदी व 100 ग्राम सोने के गहने, दलौदा में एक प्लॉट मिला है। इसके अलावा बैंकों के 10 खाते भी मिले हैं। प्रबंधक का वेतन महज 20 हजार रुपये प्रतिमाह है। 20 साल की नौकरी में 18 लाख रुपये ही वेतन होता है। लोकायुक्त संगठन उज्जैन निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर 15 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। घर की तलाशी लेकर गहने, नकदी, जमीन से जुड़े कागजात व अन्य सामान एक जगह एकत्र कर गिनती शुरू की। जमीन, दो ट्रैक्टर, 1 आई 20 कार, चार मोटरसाइकिल भी मिली हैं। नंदकिशोर धाकड़ की अब अनुपातहीन संपत्ति जांच की जाएगी।

नंदकिशोर धाकड़

'धाकड़' कमाई

- **100** ग्राम सोने के गहने
- **5000** वर्गफीट में बना दो मंजिला आलीशान बंगला
- **3** लाख रुपये नकद
- **3** किलो चांदी
- **10** बैंक खाते
- **1** कार,
- **2** ट्रैक्टर
- **4** बाइक

पगार : 20 हजार रुपए प्रति मह

ग्राम लदूसा में प्रबंधक के घर नकदी, गहने, जमीन के कागजात की जांच करती टीम। ●नवदुनिया

पूर्व में निलंबित भी हो चुका है

गांव धुधड़का की सोसायटी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रही है। यहां खाद घोटाला, कृषि ऋण घोटाले सहित कई मामले उजागर हो चुके हैं। समिति प्रबंधक नंदकिशोर धाकड़ इस मामले में निलंबित भी हो चुका है, पर राजनीतिक प्रभाव के चलते वह बहाल होता रहा और यहीं जमा रहा।

Badri Gautam

आधुनिक लैब में प्रयोग करेंगे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज : विद्यार्थियों को एसजीएसआइटीएस के प्रोफेसर भी करेंगे मदद, कोई शुल्क नहीं लेंगे

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी प्रदेश के सबसे बड़े आटोनोमस संस्थान की लैब में नए प्रयोग कर सकेंगे। गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस (एसजीएसआइटीएस) ने विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए अपनी सभी तरह की लैब उन्हें निशुल्क देने की पहल की है। संस्थान केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, फार्मेसी, बायोमेडिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सहित 15 कोर्स करवाता है। उसके पास 100 से ज्यादा लैब हैं।

संस्थान के निदेशक डा. राकेश सक्सेना का कहना है कि इन लैब का उपयोग स्कूली विद्यार्थी उस समय कर सकेंगे जब कालेज के विद्यार्थी कक्षाओं में रहते हैं या जब परीक्षाएं संचालित होती हैं। हमारे प्रोफेसर भी स्कूल के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में प्रयोग बताने के लिए मौजूद रहेंगे। डा. सक्सेना ने कहा कि हमारे पास सभी विषयों में आधुनिक लैब और साधन हैं।

Badri Gautam

एसजीएसआइटीएस में इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया है। ● **नईदुनिया**

संस्थान के आइटी विभाग की लैब में प्रशिक्षण लेते विद्यार्थी। ● **नईदुनिया**

एक समय में 100 विद्यार्थी लैब का कर सकेंगे उपयोग

संस्थान के निदेशक का कहना है कि जिन सरकारी स्कूलों को लैब का उपयोग करना है, इसके लिए वे संस्थान में आवेदन दे सकते हैं। पहले भी कई स्कूली विद्यार्थी लैब का उपयोग करने के लिए आते रहे हैं। इससे हमने सभी सरकारी स्कूलों की जरूरत को समझते हुए लैब का उपयोग उन्हें निशुल्क देने का निर्णय लिया है। एक समय में 100 से ज्यादा विद्यार्थी लैब का उपयोग कर सकेंगे।

इस तरह की लैब उपलब्ध है संस्थान के पास

नैनो टेक्नोलाजी लैब, वाटर रिर्सोसेस, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट लैब, कांक्रीट और हाइवे लैब, जियोलाजी लैब, वाइब्रेशन और नाइस कंट्रोल, मटेरियल साइंस लैब, आइसी इंजन लैब, अल्ट्रा साउंड थैरेपी, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, सीएडी लैब, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लैब सहित कई विषयों में रिसर्च करने के लिए संस्थान के पास आधुनिक लैब उपलब्ध हैं।

पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने का समय कल तक

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जारी होने वाली पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) देने का आखिरी मौका 28 फरवरी को है। प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले पेंशनधारकों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि एक मार्च के बाद उनके खातों में पेंशन की राशि जमा नहीं होगी। उधर 80-85 पेंशनधारकों ने सर्टिफिकेट बैंक में जमा करा दिया है।

संक्रमण के चलते ईपीएफओ मुख्यालय ने जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में अक्टूबर 2020 में मामूली बदलाव किया। नई गाइडलाइन जारी करते हुए विभाग ने एक नवंबर को जीवन प्रमाण पत्र देने की अनिवार्यता खत्म कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक अब पिछले जीवन प्रमाण पत्र की जारी तारीख से उसकी वैधता एक साल की रहेगी। इसके पीछे वजह यह थी कि एक नवंबर को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था। ऐसे में कार्यालय व बैंकों में कम भीड़ न उमड़ें। इसलिए नियमों में बदलाव किया है। यहां तक ईपीएफओ ने बैंकों-पोस्ट ऑफिस को भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

नहीं बढ़ाई तारीख : संक्रमण के चलते पहले ही विभाग ने प्रमाण पत्र देने के लिए एक नवंबर से 28 फरवरी तक का समय दिया था। मगर बीते दिनों पेंशनर्स एसोसिएशन ने इसकी मियाद बढ़ाने की मांग की, लेकिन ईपीएफओ के दिल्ली मुख्यालय की तरफ अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी तारीख नहीं बढ़ाई है।

अधिकांश ने दिया प्रमाण पत्र : इंदौर कार्यालय में करीब 70 हजार पेंशनधारक का पंजीयन है। एक नवंबर से 25 फरवरी तक 48 हजार से ज्यादा पेंशनधारकों ने बैंक-डाकघर में जाकर जीवित होने का प्रमाण दे दिया है। करीब 80 फीसद पेंशनधारकों ने प्रक्रिया पूरी कर ली है।

घर पहुंच सुविधा भी

बैंकों व डाकघर में जाकर जीवन प्रमाण पत्र देने की सुविधा रखी है। मगर बुजुर्गों का भी ध्यान रखा है, जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत आती है। इनके लिए जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा घर तक पहुंचाने का काम किया है। ये सुविधा डाक विभाग दे रहा है। डाक विभाग की वेबसाइट व मोबाइल एप के जरिए आवेदन करना है। 48 घंटों के भीतर डाककर्मी घर आकर जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी करेगा। बस, इसके लिए पेंशनधारकों को 70 रुपये शुल्क चुकाना होगा।

Badri Gautam

जय विज्ञान | राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह के अवसर पर हुईं कई प्रतियोगिताएं

सफल होना है तो सभी विषयों में जिज्ञासा रखें: डॉ. डालिमा

संत हिरदाराम नगर

(नवदुनिया प्रतिनिधि)। यदि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो सभी विषयों को जानने की जिज्ञासा रखें। संत हिरदाराम कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. डालिमा पारवानी ने यह बात कही। डॉ. डालिमा ने कहा कि 1928 में सर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज किए जाने के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को पूरे देश में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कॉलेज में वैज्ञानिकों के जीवन पर आधारिक नाट्य प्रस्तुति, नुक्कड़, विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। निदेशक हीरो ज्ञानचंदानी ने छात्राओं को बधाई दी।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. डालिमा पारवानी। ● नवदुनिया

Badri Gautam

इंजीनियरिंग कॉलेजों का ऑनलाइन निरीक्षण कर 50 फीसद राशि बचाएगा एआइसीटीई

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों का अब ऑनलाइन निरीक्षण होगा। साथ ही कॉलेजों को मान्यता लेने के लिए आधी राशि ही खर्च करनी होगी। इसके लिए प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और व्यावसायिक कोर्स की मान्यता जारी करने वाली फीस में 50 फीसद की कटौती की गई है। आल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) द्वारा प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं।

एआइसीटीई आगामी सत्र 2021-22 की मान्यता और निरंतरता जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। एसोसिएशन आफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट (एटीपीआइ) की मांग पर एआइसीटीई ने निरंतरता की फीस को 50 फीसद कम करने का निर्णय ले लिया है। अब कॉलेजों को हर कोर्स की स्वीकृति के लिए एक लाख रुपये का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें हर कोर्स के 50-50 हजार रुपये के हिसाब से एआइसीटीई को भुगतान करना होगा। बता दें कि प्रदेश में 150 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज और 65 से अधिक पालीटेक्निक कॉलेज हैं, जिनका ऑनलाइन निरीक्षण होगा।

निरीक्षण का वीडियो भी बनाया जाएगा: कॉलेज व संस्थानों के पेपर की जांच, सरप्राइज विजिट सभी कुछ ऑनलाइन होगा। इससे प्रोसेसिंग फीस तो कम खर्च होगी, साथ ही पूरा निरीक्षण रिकॉर्डेड रहेगा। पूरे निरीक्षण का वीडियो बनाकर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे कोई भी कॉलेज या संस्था की जानकारी कभी भी हासिल कर सकेगा।

> एआइसीटीई ने मान्यता की फीस में 50 फीसद कटौती के प्रस्ताव को स्वीकृत कर कॉलेजों की काफी मदद की है। अब कॉलेजों या संस्थाओं का ऑनलाइन निरीक्षण होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
>
> **- अजीत सिंह पटेल**, कोषाध्यक्ष, एटीपीआइ

Badri Gautam

पहल | **आइआइटी गांधीनगर मप्र के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विज्ञान व गणित का देगा प्रशिक्षण**

'माटसाहब' के दिमाग की बत्ती जलाएंगे आइआइटी के प्राध्यापक

प्राध्यापकों से सीखेंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक

रोटी क्यों फूलती, स्ट्रॉ से नारियल पानी कैसे पीते हैं?

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आइआइटी के प्रोफेसर विज्ञान और गणित की छोटी-छोटी क्रियाओं को सिखाएंगे, ताकि वे बच्चों को आसानी से समझा सकें। इसके लिए दैनिक जीवन में होने वाली वैज्ञानिक क्रियाओं को उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा।

विज्ञान और गणित को बच्चों के लिए आसानी से सिखाने के लिए आइआइटी गांधीनगर में सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग (सीसीएल) ने शिक्षकों के लिए स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित) कोर्स तैयार किया है। अब आइआइटी गांधीनगर और मप्र स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विज्ञान एवं गणित विषयों की सैद्धांतिक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से तीन चरणों में प्रत्येक रविवार यू-ट्यूब के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें स्टीम आधारित एपिसोड 'दिमाग की बत्ती जला दें' कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके लिए प्रदेश के करीब 50 हजार शिक्षकों ने पंजीयन कराया है। इसमें शिक्षकों को होमवर्क भी दिए जाएंगे, जिससे वे प्रशिक्षण के बाद पूरा कर ऑनलाइन जमा करेंगे और प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मप्र बोर्ड परीक्षा में 40 फीसद से कम अंक लाने वाले स्कूलों के शिक्षकों की परीक्षा ली गई। इसमें सबसे ज्यादा विज्ञान और गणित के करीब पांच हजार शिक्षक शामिल थे। इस कारण शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि वे बच्चों को आसानी से समझा सकें।

खीरे से सिखाएं गणित : इसमें गणित को आसानी से सिखाने के लिए खीरा से सीखाया जाएगा। खीरे से त्रिभुज, सर्किल, चतुर्भुज सहित रेखागणित की बारीकियों को समझाया जाएगा। गणित में त्रिकोणमिति लहरों के माध्यम से और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ भौतिक विज्ञान के कुछ बुनियादी सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी जाएगी। गुणा, भाग, जोड़ व घटाव के तरीके अलग-अलग क्यों है, इसका कारण भी समझाया जाएगा।

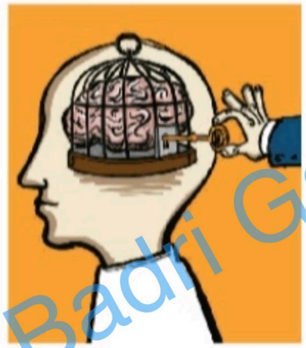

कुछ इस तरह से समझाएंगे वैज्ञानिक पद्धति

पहला उदाहरण : रोटी क्यों फूलती है, रोटी को बनाते समय उसमें ग्लूटेन रसायन उत्पन्न हो जाता है और रोटी गर्म होने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, इस कारण रोटी फूलती है।

दूसरा उदाहरण : नारियल पानी पीते समय जो हम स्ट्रा का उपयोग करते हैं तो वायु दाब के कारण हम उसे ऊपर खींच पाते हैं, अगर स्ट्रा में छेद हो जाता है तो स्ट्रॉ के बाहर और अंदर का वायु दाब बराबर हो जाता है तो हम पानी पी नहीं पाते हैं।

"बच्चों को गणित और विज्ञान से डर लगता है। इसके लिए प्रायोगिक तरीके से समझाया जाए तो आसानी होगी। छोटे-छोटे उदाहरण देकर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
– **मनीष जैन**, कोर्स प्रभारी, आइआइटी गांधीनगर

विज्ञान के साथ दैनिक जीवन को जोड़कर समझेंगे तो वह आसानी से समझ पाएंगे। छोटी क्रियाओं से गणित व विज्ञान को आसान बना सकते हैं। – **मेधा बाजपेयी**, विज्ञान संचारिका, मप्र"

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Badri Gautam

दुनियाभर की छात्रवृत्ति योजनाएं अब एक प्लेटफार्म पर

केंद्र सरकार की पहल पर आइआइआइटीडीएम के विशेषज्ञों ने तैयार की वेबसाइट

नईदुनिया विशेष

पंकज तिवारी ● जबलपुर

होनहार विद्यार्थियों की पढ़ाई की राह और आसान बनाने के लिए ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर शोध हुआ है, जो देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर की छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी व इनके लिए पंजीयन भी एक ही प्लेटफार्म पर करवाने की सुविधा देगा। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस काम का जिम्मा पं. द्वारिकाप्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंफोर्मेशन टेक्नोलाजी, डिजाइन एंड मैन्युफेक्चरिंग-आइआइआइटीडीएम) जबलपुर को सौंपा था। इसके दो विशेषज्ञों ने एक अन्य विशेषज्ञ के सहयोग से काम पूरा कर लिया है। इन्होंने एक ऐसी वेबसाइट तैयार की है, जिस पर एक साथ 10 लाख यूजर लाग-इन कर सकेंगे। वेबसाइट सितंबर 2021 से काम करने लगेगी।

डा. कौशलेंद्र सिंह

डा. रिचा दीक्षित ● नईदुनिया

> आमतौर पर भारी भरकम प्रोग्राम वाली वेबसाइट अधिकाधिक लोगों के एक साथ सर्च या लाग-इन करने पर हैंग होने लगती है। लेकिन, इस वेबसाइट पर दस लाख यूजर एक साथ विजिट कर सकेंगे। खास बात यह भी होगी कि पुरानी योजनाएं स्वतः हटती जाएंगी और नई जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी।
>
> **डा. मनीष कुमार बाजपेयी**, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग, आइआइआइटीडीएम, जबलपुर

सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फार स्कालरशिप एंड फेलोशिप नाम के इस प्रोजेक्ट को आइआइआइटीडीएम के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग ने पूरा किया है। टीम में इसी विभाग के डा. मनीष कुमार बाजपेयी, आइआइआइटीडीएम जमशेदपुर के डा. कौशलेंद्र कुमार सिंह और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर की डा. रिचा दीक्षित शामिल रहीं। इस पर 24 लाख रुपये की लागत आई है।

यह है योजना: स्कूल से लेकर कालेज एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सैकड़ों प्रकार की छात्रवृत्तियां शासकीय और निजी स्तर पर दी जाती हैं। संस्थान, इंडस्ट्री भी अपने स्तर पर छात्रवृत्तियां देते हैं। ये छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों, शोधार्थियों को राज्य, केंद्र एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से दी जाती हैं। भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीयकृत व्यवस्था बनाने का जिम्मा दिया था। इसमें सभी छात्रवृत्तियों की जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी। संबंधित एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थी सभी छात्रवृत्ति से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

सिस्टम ऐसे करेगा काम: ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से जुड़ा होगा, जो स्वयं ही अपग्रेड करता रहेगा। यह विश्व में कहीं से भी जारी की गई भारतीय मूल के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी छात्रवृत्ति योजना के बारे में भी जानकारी संकलित कर प्रस्तुत करेगा। इसमें पुरानी योजना स्वतः ही हट भी जाएगी।

Badri Gautam

सीटीईटी के नतीजे घोषित, डिजिटल अंकसूची जारी

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं। 31 जनवरी 2021 को आयोजित परीक्षा के नतीजे डिजिलॉकर में उपलब्ध कराए गए हैं। सीटीईटी परीक्षा के सचिव ने जारी आदेश में कहा कि अंकपत्र और पात्रता प्रमाण पत्र डिजिटल स्वरूप में दिए जाने से डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

Badri Gautam

अनुकंपा नियुक्ति में हीलाहवाली कटनी डीईओ को पड़ी भारी

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अनुकंपा नियुक्ति में हीलाहवाली पर न्यायालय ने भी नाराजगी जाहिर की। लोक शिक्षण संचालनालय से आयुक्त को खुद पेशी करनी पड़ी। इतने सब होने के बाद अब विभाग ने पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कटनी जिला शिक्षा अधिकारी का तबादला कर दिया है। उन्हें कटनी से जबलपुर लोक शिक्षण जबलपुर संभाग अटैच किया गया है। उनकी जगह पर कटनी का प्रभार शशीबाला झा प्राचार्य डाइट को दिया गया है।

आयुक्त के द्वारा जारी तबादला आदेश में कहा गया है कि शिखा शर्मा के अनुकंपा प्रकरण में अवमानना याचिका लगी। इसमें न्यायाधीश ने भी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद विभाग ने बृजबिहारी दुबे प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को कटनी से मुक्त करते हुए कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग में रिक्त सहायक संचालक के पद पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है।

Badri Gautam

बच्चों में विज्ञान विषय को लेकर जागरूकता पैदा करने स्कूलों में आयोजित होंगी विभिन्न गतिविधियां

जबलपुर (नईदुनिया रिपोर्टर)। बच्चों की कल्पनाओं और उनके आइडिया को साकार करने का बेहतर अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए इस बार की थीम बच्चों पर ही आधारित है। आम तौर पर विज्ञान बड़ा ही रोचक विषय है, लेकिन इस विषय से बच्चे ही रुचि बढ़ती उम्र के साथ कम होती जाती है, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है कि इसमें धैर्य के साथ काम करने की जरूरत होती है। बच्चे अपनी शिक्षा को पूरा करते ही अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, जिसके लिए वे ऐसे क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। जहां उन्हें जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाए। जिसके चलते वे अपने विज्ञान विषय को पीछे छोड़ देते हैं। शोध करने वालों की घटती संख्या का यह एक बड़ा कारण है। बच्चों की कम होती हुए रुचि को देखते हुए ही इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है विज्ञान, तकनीक, नवाचार: शिक्षा, कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। जिसके अंतर्गत स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर विज्ञान के क्षेत्र में उनका कौशल विकास करने का प्रयास करना होगा ताकि बच्चे इस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें।

अटल टिंकरिंग लैब से होगा नवाचार : शहर के केन्द्रीय विद्यालय सीएमएम के प्राचार्य एसके नामदेव ने बताया कि विज्ञान दिवस की थीम काफी अच्छी हैं। अटल टिंकरिंग लैब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लैब में बच्चे अपने नवाचार को लेकर काम कर पाएंगे। इससे निश्चित ही बच्चों की रुचि विज्ञान विषय पर बढ़ेगी और वे आगे इस क्षेत्र में बेहतर काम कर पाएंगे। साल भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि इनमें बच्चों की सहभागिता बनी रहे।

सही मार्गदर्शन मिलने की है जरूरत: सहोदय अध्यक्ष डॉ.राजेश कुमार चंदेल ने बताया कि विज्ञान में हर एक बच्चे की रुचि होती है, लेकिन समय के साथ उनकी रुचि बदल जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वालों की संख्या घटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों की रुचि कम हुई है। आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सभी के आने से बच्चे विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन वे सही अवसर की तलाश कर नौकरी करने मे जुट जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी बेहतर अवसर मिलने चाहिए कि युवा इससे जुड़े रहे और इस क्षेत्र में काम कर पाएं। इसके लिए आईआईटी, एनआईटी की तरफ से अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। सही मार्गदर्शन मिलने से ही इस क्षेत्र में नवाचार देखने को मिल सकता है।

टॉय फेयर के लिए शहर की शिक्षिका नेहा सिंह ने बताया डीएनए टॉय। ● सौजन्य

टॉय फेयर को लेकर है उत्साह

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के पूर्व 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल रूप से टॉय फेयर पूरे देश में शुरू किया गया। इसे लेकर शहर के बच्चों और शिक्षकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न स्कूलों और शिक्षकों ने विज्ञान से जोड़ते हुए खिलौनों को तैयार किया है और अपने आइडिया को टॉय फेयर में प्रस्तुत किया है। शहर की एक निजी स्कूल की शिक्षिका नेहा सिंह जो कि बायो पढ़ाती है। इन्होंने भी टॉय फेयर के लिए डीएनए टॉय तैयार किया है। जिसे इन्होंने काफी कम पैसों से तैयार किया है। यह देखने में बेहद खूबसूरत है और यह शरीर में डीएनए की स्थिति को भी बताता है।

Badri Gautam

प्रदेश के 52 जिलों में विज्ञान यात्रा की शुरुआत आज आइआइटी से

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी (आइआइटी) इंदौर, विज्ञान भारती और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा 11 से 13 मई तक मध्यप्रदेश विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2021 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रदेशभर में विज्ञान यात्रा की जा रही है। इसकी शुरुआत रविवार को दोपहर तीन बजे आइआइटी परिसर से होगी। संस्थान ने इसके लिए एक विज्ञान बस तैयार की है जो प्रदेश के 52 जिलों में जाएगी और वहां के लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, भारत सरकार के एसटीपीआइ के महानिदेशक डा. ओमकार राय, आइआइटी इंदौर के कार्यवाहक निदेशक प्रो. निलेश कुमार जैन, आइआइटी इंदौर के छात्र कल्याण विभाग के डीन डा. संतोप कुमार विश्वकर्मा, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. सुधीर एस. भदौरिया सहित आइआइटी इंदौर के प्रोफेसर और अन्य संस्थानों के शिक्षक मौजूद रहेंगे।

अनूठी पहल

- 11 से 13 मई तक होगा मध्यप्रदेश विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी
- आयोजन से पहले विभिन्न जिलों में पहुंचकर जानकारी देगी विज्ञान बस

आज 56 दुकान पर देख सकेंगे विज्ञान के चमत्कार

विज्ञान यात्रा के लिए विज्ञान के प्रयोग और इतिहास को वताने के लिए यह विशेष वस तैयार की गई है। वस में विज्ञान से संबंधित कई प्रयोगों को दर्शाया गया है। वस में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की जानकारी दी गई है। 28 फरवरी को आइआइटी से निकलकर वस शाम पांच बजे सी-21 माल पर आएगी। इसके वाद रात 10 वजे तक 56 दुकान पर मौजूद रहेगी। वस में लगाई गई एलईडी पर विज्ञान विषयों पर वनाई गई शार्ट स्टोरी प्रसारित की जाएगी। 11 मई को वस विभिन्न जिलों से होते हुए वापस इंदौर पहुंचेगी। विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में शामिल होने का मौका भी विद्यार्थी और शिक्षकों को मिलेगा। इसमें 52 श्रेष्ठ टेक्नोलाजी पुरस्कार दिए जाएंगे।

Badri Gautam

हाई कोर्ट ने कहा– 'नगरीय निकाय के लिए 50 फीसद से अधिक नहीं हो सकता आरक्षण'

फैसला ● धनपुरी नगर परिषद के लिए वार्ड आरक्षण का नोटिफिकेशन निरस्त

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए किसी सूरत में ओबीसी, एससी, एसटी को मिलाकर कुल 50 फीसद से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने साफ किया कि 50 फीसद का यह बंधन सिर्फ संविधान की पांचवीं अनुसूची में वर्णित आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतों के लिए तोड़ा जा सकता है। लेकिन सामान्य क्षेत्र के नगरीय निकायों के लिए यह बंधन तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मत के साथ कोर्ट ने शहडोल जिले की धनपुरी नगर परिषद के लिए जारी वार्ड आरक्षण का नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को सात की जगह छह सीटें आरक्षित करते हुए फिर से वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया की जाए।

धनपुरी शहडोल निवासी मोहम्मद आजाद की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि सुको के निर्देश व संविधान की मंशा के अनुसार नगरीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन 10 दिसम्बर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी कर धनपुरी नगर परिषद के तीन वार्ड एससी, पांच वार्ड एसटी व सात वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिए गए। जबकि नगर परिषद में कुल 28 वार्ड

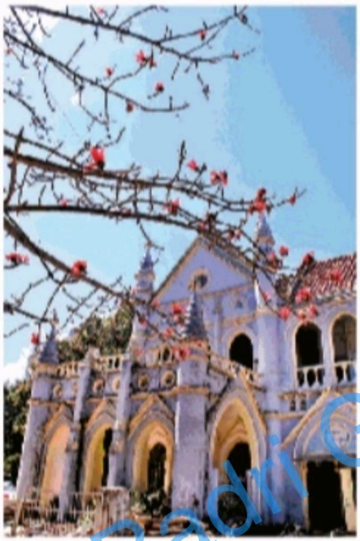

हैं। नियमों के अनुसार 14 से अधिक वार्ड आरक्षित नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायदृष्टांतों का हवाला दिया गया। आग्रह किया गया कि नियम विरुद्ध किये गए वार्ड आरक्षण का नोटिफिकेशन निरस्त कर फिर से विधिवत तरीके से वार्ड आरक्षण किया जाए। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त नोटिफिकेशन को असंवैधानिक पाकर निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार के 29 अगस्त 2019 को जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए सात की जगह छह वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित करते हुए पूरी आरक्षण प्रक्रिया फिर से पूरी की जाए। इसके लिए कोर्ट ने 15 दिनों का समय दिया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव व चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ उपस्थित हुए।

हाई कोर्ट ने खारिज की नगर परिषद आरक्षण के खिलाफ जनहित याचिका

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर परिषद आरक्षण के खिलाफ दायर जनहित याचिका सारहीन पाते हुए खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता टीकमगढ़ निवासी अमित नायक की ओर से अधिवक्ता मयंक श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नगर परिषद लिधौरा खास, जिला टीकमगढ़ के अध्यक्ष पद की सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित कर दी गई है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या के हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण पर विचार नहीं किया गया। पूर्व में भी ऐसा ही किया गया था। बावजूद इसके कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या 11162 में से 3311 अजा, 271 अजजा, 1560 ओबीसी व 6020 जनसंख्या सामान्य है। बहस के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र यादव ने जनहित याचिकाकर्ता के तर्क का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आरक्षण के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है। सिर्फ जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर विधिवत आरक्षण को चुनौती देना अनुचित है।

होमगार्ड सैनिकों को नियमित किए जाने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से होगी

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होमगार्ड सैनिकों को नियमित किए जाने के मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में दायर याचिकाओं को भी मुख्य पीठ जबलपुर में रेफर करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। जबलपुर निवासी तूफान सिंह सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया है कि लंबे समय से होमगार्ड सैनिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया है कि होमगार्ड सैनिकों को हर साल दो महीने के लिए बैठा दिया जाता है। याचिका में होमगार्ड सैनिकों को नियमित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंजली बैनर्जी, संजय के अग्रवाल व डीके दीक्षित पैरवी कर रहे हैं।

Badri Gautam